

प्रेषक,

विनोद फोनिया,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास निदेशालय,
उत्तराखण्ड पीडी।

ग्राम्य विकास अनुभाग।

देहरादून, दिनांक 26 दिसम्बर, 2014

विषय— जनपद बागेश्वर की रिखाड़ी-बाछम मोटर मार्ग के विभिन्न स्थानों पर 09 बैली ब्रिजेज के निर्माण हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबाई) के पत्र संख्या NB-SPD/RIDF-XX (Uttarakhand) /144 PSC Dt. 11.11.2014 द्वारा जनपद बागेश्वर के रिखाड़ी- बाछम मोटर मार्ग के विभिन्न स्थानों पर 09 बैली ब्रिजेज, जिसकी कुल लागत ₹ 1989.99 लाख है, जिसमें से ₹ 1790.99 लाख नाबाई द्वारा तथा ₹ 199.00 लाख राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाना है, की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2— अतः उक्त बैली ब्रिजेज के निर्माण हेतु ग्राम्य विकास विभाग के अर्न्तगत संचालित प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) " योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2014-15 में प्राविधानित बजट की धनराशि में से ₹ 1989.99 लाख (एक उन्नीस करोड़ नवासी लाख निम्नानवे हजार मात्र) की धनराशि आपके निर्वहन पर रखते हुये निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन नियमानुसार व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

- 1— इस शासनादेश द्वारा अवमुक्त की जा रही धनराशि को तत्काल आहरित कर नियमानुसार व्यय किये जाने हेतु मुख्य अभियन्ता, यूआरआरडीए के निर्वहन पर रखा जाना सुनिश्चित करें।
- 2— कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।
- 3— कार्य पर मदवार मदवार उतना ही व्यय किया जाए जितनी मदवार धनराशि स्वीकृत की गई है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाए।
- 4— कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।
- 5— निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाए तथा विशिष्टियों के अनुरूप सामग्री ही प्रयोग में लायी जाए।
- 6— विस्तृत आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित कार्यदायी संस्था पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी।
- 7— स्वीकृत विस्तृत आगणन के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के आगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य स्थिति की दशा में ही) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाए।
- 8— मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं० 2047/XIV-219(2006) दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें।
- 9— आगणन गठित करते समय तथा कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
- 10— ₹ 632.36 लाख के अतिरिक्त आगणन में प्राविधानित धनराशि ₹ 1351.77 लाख के कार्यों हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के अनुसार कार्यवाही की जाए।

कमरा:.....2

- 11- इस सम्बन्ध में नाबार्ड द्वारा निर्गत सम्बन्धित नियमों/दिशा निर्देशों/प्रतिबन्धों का शतप्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- 12- इस सम्बन्ध में नाबार्ड से प्राप्त धनराशि का लेखा-जोखा पृथक से रखा जायेगा, तथा नाबार्ड की शर्तों के अनुरूप प्रतिपूर्ति सुनिश्चित की जायेगी।
- 13- चूंकि प्रश्नगत वैली ब्रिज के प्रस्ताव/आंगणन वर्ष 2013 में राज्य में आयी आपदा को देखते हुये आपात स्थिति के मुताबिक तत्काल निर्माण किये जाने हेतु गठित/प्रस्तावित किये गये थे, लेकिन वर्तमान/इस समय कोई आपात स्थिति नहीं है, इसलिये मुख्य कार्यकारी अधिकारी, यूआरआरडीए द्वारा अपने स्तर से वैली ब्रिज के लिये गठित आंगणन में रखे गये दरों का लोक निर्माण विभाग की दर के हिसाब से तकनीकी परीक्षण करावेंगे, तथा तकनीकी परीक्षण के उपरान्त इनकी दर औचित्यपूर्ण पाये जाने पर ही प्रश्नगत निविदा को स्वीकृत करते हुये अवाई आदि किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
- 3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के अनुदान सं०-19 के लेखाशीर्षक 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय-102-सामुदायिक विकास -01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-0106-प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) 24-वृहत निर्माण कार्य के अन्तर्गत वहन किया जायेगा।
- 4- यह आदेश वित्त विभाग-1 के शासनादेश संख्या- 183/XXVII-1/2012 दिनांक 28 मार्च, 2012 के अधीन साफ्टवेयर से केन्द्रीय स्तर पर एक विशिष्ट नम्बर अलॉटमेंट आईडी0 S1412190251 जनरेट कर जारी किये जा रहे हैं।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या 11(P)XXVII-4/14 दिनांक 22 दिसम्बर, 2014 द्वारा दी गयी सहमति के क्रम में जारी किया जा रहा है।

(विनोद कोनिया)
सचिव।

संख्या एवं दिनांक-यथोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- मुख्य अभियन्ता, यूआरआरडीए0, सहस्रधारा रोड, देहरादून।
- 2- मुख्य अभियन्ता स्तर-1, (कुमार्यु), अल्मोड़ा, (गढ़वाल मण्डल) देहरादून।
- 3- निदेशक कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड।
- 4- वित्त अनुभाग-1 उत्तराखण्ड शासन।
- 5- मुख्य कोषाधिकारी, पीडी गढ़वाल।
- 6- आयुक्त, गढ़वाल/कुमार्यु।
- 7- प्रभारी एनआईसी0, देहरादून।
- 8- बजट राजकोषीय नियोजन, सचिवालय देहरादून।
- 9- महालेखाकार (लेखा एवं लेखा परीक्षा) माजरा, देहरादून।
- 10- महालेखाकार (माजरा) उत्तराखण्ड वैभव पैलेस सी-1/105 इन्दिरा नगर देहरादून।
- 11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(सत्यप्रकाश सिंह)
अनु सचिव।

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20142015

Secretary, Rural Development (S041)

अलॉटमेंट आई डी - S1412190251

आवंटन पत्र दिनांक - 24-Dec-2014

आवंटन पत्र संख्या - /xl/14/56(01)2013T.C.II

संयुक्त संख्या - 019

HOD Name - Rural Development Commissioner (2252)

लेखा शीर्षक 4515 - ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय

00 -

102 - सामुदायिक विकास

01 - केन्द्रीय आयोजनामार्फत द्वारा पुरोनिधानित योजना

06 - प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY)

Plan Voted

संयुक्त ग्रेड का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
14 - ग्राम विधायक कार्य	1540410000	1989990000	1739409000
	1540410000	1989990000	1739409000

Total Current Allotment To Head Of The Department In Above Schemes -

1989990000